विचार बिन्दु

जो तेरे सामने और की निंदा करता है, वो और के सामने तेरी निंदा करेगा।
–कहावत

पृथ्वी के स्वर्ग ''कश्मीर'' पर बढ़ता दबाव

लगभग एक दशक बाद पुनः कश्मीर आने का संयोग बना और इस समय मैं यहां कश्मीर से ही पाठकों हेतु यह आलेख भेज रहा हूँ। आप में से कई ने कश्मीर अवश्य देखा होगा और सभी निश्चित रूप से इसे 'पृथ्वी का स्वर्ग' कहे जाने से पूर्णतया सहमत हुए होंगे। जो नहीं भी आ पाए होंगे, उन्होंने ने भी बॉलीवुड फ़िल्मों के माध्यम से इसके दर्शन अवश्य किए होंगे। इस आलेख का उद्देश्य प्रमुख रूप से वर्तमान हालात से पाठकों को अवगत कराना एवं इस बदलाव के कारण भविष्य में संभावित परिणामों के बारे में जानकारी देना है।

वर्ष 1989 में आतंकवाद का प्रारंभ कश्मीर में हुआ और उसकी शुरुआत कश्मीर घाटी से पंडितों को प्रताड़ित कर कश्मीर घाटी को छोड़ने पर मजबूर करने से हुई। इस पलायन पर बहुत कुछ लिखा गया है एवं हाल ही में एक फिल्म 'कश्मीर फाइल' नाम से बनी है, जिसमें उस समय के दृश्यों का बहुत ही प्रभावी तरीके से चित्रण किया गया है।

इस तथ्य से सभी अच्छी तरह परिचित हैं कि 1989 से जो आतंकवाद प्रारंभ हुआ, उसका सर्वाधिक नुकसान यहां के पर्यटन को हुआ। उल्लेखनीय है कि कश्मीर की पूरी अर्थव्यवस्था एवं रोजगार का माध्यम यहां पर आने वाले पर्यटक ही थे। तब से अब तक आतंकवाद की नियमित घटनाओं के कारण यहां पर्यटकों की स्थिति कम-अधिक होती रही। कई वर्षों के आतंकवाद के कारण जहां पर्यटक लगभग नगण्य हो गए थे। यहां के युवक बेरोजगार हो गए और अर्थव्यवस्था भी ध्वस्त हो गई। जब कभी लगता कि स्थिति सामान्य हो रही है, पर्यटक आना प्रारंभ करते, किंतु फिर कोई बड़ी आतंकवादी घटना हो जाती और फिर से इस पर विराम लग जाता। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने संविधान से धारा 370 हटाकर, जम्मू कश्मीर को मिले विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया । इसके साथ ही विधानसभा को भंग कर दिया तथा जम्मू कश्मीर को एक राज्य से केंद्र- शासित प्रदेश बना दिया गया। लद्दाख को जम्मू कश्मीर राज्य से अलग, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसके घोर विरोध की आशंका के कारण यहां के सभी राजनीतिक नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को जेलों में बंद कर दिया गया तथा इन्टरनेट पर रोक लगा दी गई, जो एक साल से अधिक समय तक रही। विधानसभा को भंग करने से परिणाम स्वरूप कश्मीर का शासन सीधे केंद्र सरकार के हाथ में आ गया। इन्टरनेट बंद होने से सारी व्यापारिक गतिविधियां थम गईं। जनजीवन एक प्रकार से समाप्त ही हो गया। इसके बाद यहां पर भारी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखते हुए धीरे-धीरे इंटरनेट में छूट दी गई और नेताओं को भी धीरे-धीरे रिहा किया गया।

इसके बाद मार्च, 2020 में कोरोना के कारण पर्यटन बंद ही रहा । इस अवधि में आतंकवादी घटनाओं में बहुत कमी आई जिससे वर्ष 2022 में रिकॉर्ड तोड़ लगभग 1.88 करोड़ पर्यटक कश्मीर घाटी में आये । इस वर्ष यह संभावना है कि यह संख्या और भी अधिक होगी।

6 अप्रैल, 2023 को हम श्रीनगर पहुंचे तो सबसे पहले जिस बात पर हमारा ध्यान गया वह था हजारों वाहनों की रेलमपेल। हमें लगा ही नहीं कि किसी ऐसे स्थान पर पहुंचे हैं जो आतंक से लंबे समय तक त्रस्त रहा है। पूरा जनजीवन सामान्य दिखाई दिया। वाहनों की और पर्यटकों की भीड़ के कारण कुछ ऐसा माहौल था जैसा जयपुर जैसे शहरों में सामान्यता दिखाई देता है। केवल एक अंतर अवश्य था, सेना और सुरक्षा बलों की भारी तैनाती। किंतु इसके कारण लोगों में भय का भाव नहीं था। रमजान का महीना होने के बावजूद बाजार खुले थे और पर्यटकों को खरीदारी करने में कोई परेशानी नहीं थी। वाहनों की संख्या तो इतनी अधिक थी कि कई स्थानों पर ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति बन गई। ऐसा लग रहा था जैसे देश के अन्य भागों के लोग कितने सालों की कसर पूरी करने के लिए कश्मीर आ रहे हैं । कश्मीर का मौसम बहुत अनिश्चित है । हमें यह बताया था कि बहुत ठंड पड़ रही है और बारिश है और हम उसी तैयारी से आए थे, किंतु यहां का तापमान लगभग सामान्य था । इसका एक कारण शायद पर्यटकों की बढ़ती संख्या भी हो सकता है ।

पहाड़ को काटे जाने और निर्माण कार्य के दृश्य श्रीनगर और इसके बाहरी क्षेत्रों में दिखाई दिए। हाल ही में कश्मीर के बाहर के लोगों को यहां सम्पत्ति खरीदने की छूट दी गई है। अब तक कश्मीर के बाहर के लोग यहां सम्पत्ति क्रय नहीं कर सकते थे। बहुत बड़े होटल ग्रुप के होटल यहां बनने लगे हैं। स्थानीय लोगों से बात करने का प्रयास किया तो ऐसा लगा कि उनके मन में कसक और आशंका है। जो भूमि उन्हीं के लिए थी, उनसे छिन जाएगी। अब उस पर कई अन्य लोग आ जाएंगे और शायद धीरे-धीरे पूरे घाटी पर बाहरी लोगों का आधिपत्य हो जाएगा। बाहरी व्यक्तियों के बड़ी संख्या में आने से स्थानीय लोग मालिक से नौकर की स्थिति में आ जाएंगे। यह भी आशंका है कि रोजगार बढ़ा अवश्य है, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि उनके रोजगार बाहरी लोगों को चले जाएं। यहां के लोग तात्कालिक स्वार्थ में अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेच दें और अपने ही भूमि पर एक प्रकार से दूसरे दर्जे के नागरिक बनकर रह जायें।

इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता है, तत्काल पर्याप्त संसाधन जुटाकर यहां के पर्यटन स्थलों को सुंदर और स्वच्छ बनाने के साथ ही उनके संधारण की प्रभावी व्यवस्था की जाये। हेतु यहां के नीति निर्धारकों को विश्व के अन्य देशों से सीखना होगा कि कैसे अत्यधिक दबाव के बावजूद पर्यटक स्थलों को स्वच्छ और सुविधाओं से युक्त रखा जा सकता है।

पर्यटकों की दृष्टि से बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। पर्यटकों की अत्यधिक बढ़ती संख्या के अनुरूप पर्यटन स्थलों के संधारण की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। सरकार को चाहिए कि कश्मीर के विभिन्न पर्यटन स्थलों की भार वहन करने की क्षमता का आकलन करें एवं उसी अनुसार आधारभूत पर्यटन सुविधाएं उपलब्ध कराएं, जिनमें विशेष रूप से पर्याप्त संख्या में स्वच्छ शौचालय की सुविधा है। प्रत्येक पर्यटन स्थल के लिए अधिकतम पर्यटकों की संख्या निर्धारित करना उचित होगा। इसके अभाव में, पर्यटक जिस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने आते हैं, वही नहीं रहेगा। यह वैसा ही होगा, जैसे रोज़ सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को ही लालच में एक बार में ही मार दिया जाय।

एक और बात मैंने यह अनुभव की कि पर्यटकों से जितने भी आय होती है, उसका अधिकांश हिस्सा विभिन्न स्तर के बिचौलियों को चला जाता है। ये बिचौलिए टूर गाइड, बड़े ठेकेदारों, समाज के प्रभावशाली व्यक्ति, यहां के नेता, अधिकारी और यूनियन के नेता हो सकते हैं। एक उदाहरण देना उपयुक्त होगा। गुलमर्ग में बर्फ पर स्कूटर चलाने वालों से पता किया तो ज्ञात हुआ कि उन्हें केवल 15000 प्रति माह मिलते हैं, जबकि प्रत्येक पर्यटक से 15-20 मिनट की राइड के लिए 1000 लिए जाते हैं। यदि एक स्कूटर एक दिन में 10 राइड भी कराए तो एक स्कूटर से 10000 की आय प्रतिदिन की होती है। इसका अर्थ हुआ कि मेहनत करने वाले व्यक्ति को कुल आय का 5 प्रतिशत ही पहुंचता है। इसी प्रकार ड्राइवर को 7000 महीना ही प्राप्त होता है जो बहुत ही कम है। आय का अधिकांश भाग ठेकेदारों, यूनियन-पदाधिकारियों को चला जाता है।

कश्मीर के संबंध में निर्णय लेने वाली संस्थाओं एवं अधिकारियों यह जरूर सोचना होगा कि पर्यटन से होने वाली आय का समुचित हिस्सा यहां के स्थानीय निर्धन नागरिकों को मिले, विशेष कर मेहनत करने वालों को जैसे होटल में सामान ढोने वाले, वेटर, ड्राइवर, हस्तशिल्प उत्पाद बनाने वाले कारीगरों, स्लेज गाड़ी या स्नो स्कूटर चलाने वालों आदि को मिले। इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो इन्हें देश विरोधी ताकतों द्वारा भ्रमित करने का कार्य सरलता से किया जा सकता है। आतंकवाद की जड़ों में, अन्य बातों के अलावा, स्थानीय नागरिकों की निर्धनता मुख्य भूमिका निभाती है। रोजगार के प्रति युवा अगर आश्वस्त होगा तो उसे बरगलाना आसान नहीं होगा। मेरा पहले भी विश्वास था कि जो इस बार और दृढ़ हुआ है कि कश्मीर के लोग बहुत भोले और सीधे हैं। बस, केवल उन्हें विश्वास में लेने और उसे बनाए रखने की आवश्यकता है।

श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन का विकास पर्यटकों के लिए अतिरिक्त बड़ा आकर्षण सिद्ध हो रहा है यहां लगभग 16 लाख ट्यूलिप के पौधे लगाए गए हैं जो बहुत सुन्दर दिखाई देते हैं। किन्तु, पूरे श्रीनगर शहर को अच्छा हरा-भरा बनाने की आवश्यकता है।

यहां एक बात और लिखना उपयुक्त होगा। श्रीनगर की डल झील, जिसके कारण इसे पृथ्वी का स्वर्ग कहा गया, वह बहुत गंदी हो चुकी है और उसके पानी की स्वच्छता जो कश्मीर के स्वभाव के अनुरूप होनी चाहिए, वह धीरे-धीरे लुप्त हो गई है। हाउसबोट होना और पर्यटकों को सुविधाएं देना बहुत अच्छी बात है किन्तु उसके कारण वातावरण को प्रदुषित कर देना प्रकृति के साथ अन्याय है। आज के वैज्ञानिक और तकनीकी युग में संभव होना चाहिए कि इस झील के पानी को किस प्रकार उपचारात्मक तरीके से स्वच्छ बनाए रखा जा सके।

इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता है, तत्काल पर्याप्त संसाधन जुटाकर यहां के पर्यटन स्थलों को सुंदर और स्वच्छ बनाने के साथ ही उनके संधारण की प्रभावी व्यवस्था की जाये। हेतु यहां के नीति निर्धारकों को विश्व के अन्य देशों से सीखना होगा कि कैसे अत्यधिक दबाव के बावजूद पर्यटक स्थलों को स्वच्छ और सुविधाओं से युक्त रखा जा सकता है।

सरकार और कश्मीरी लोग मिलकर ही पृथ्वी के स्वर्ग को स्वर्ग बनाए रख सकते हैं। कश्मीरी लोगों के सुखद भविष्य की अनेकानेक शुभकामनाएं।

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

महात्मा जोतिबा फुले एवं डॉ. अंबेडकर जयंती अवसर पर विशेष

'क्यों नहीं बना पाए फुले और अंबेडकर के सपनों का समतामूलक भारत?'

डॉ. रमेश बैरवा

11 अप्रैल और 14 अप्रैल को क्रांतिकारी विचारक एवं समाज सुधारकों के जन्मदिवस हैं। 11 अप्रैल को ''गुलामगिरी,किसान का कोड़ा, अछूतों की कैफियत'' जैसी प्रसिद्ध कृतियों के लेखक, 'सत्य शोधक समाज' के संस्थापक, मजदूर, किसान, दलित, पिछड़े वर्ग के हितैषी तथा मुस्लिम परिवार उस्मान शेख और उसकी बहन फातिमा शेख के सहयोग से सावित्री बाई के साथ महिला शिक्षा की अलख जगाने वाले क्रांतिकारी समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्मदिन है। 14 अप्रैल को 'जाति उन्मूलन' चाहने वाले,दलित मुक्ति के लिए 'पूंजीवाद और जातिगत भेदभाव' के खिलाफ वैचारिक संघर्ष को जरूरी मानने वाले, संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ.भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है। इन्हें तहेदिल से अभिवादन।

इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब-जब भी इस धरती पर जुल्म बढ़ा है, तो जुल्म के खिलाफ शोषित, पीड़ित आमजन ने जंग लड़ी है, जिसमें जीत भी मिली है, जिसका नेतृत्व करने वाले नायक का नाम इतिहास के अमिट अक्षरों में अंकित हुआ है। यह भी हकीकत है कि जुल्म, ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाने के लिए इंसान को कई बार यातनाएं भी मिली हैं, कुर्बानियां भी देनी पड़ी हैं लेकिन इस सबकी बदौलत ही दुनिया में क्रांतियां हुई हैं, बदलाव आया है। बुनियादी बदलाव सिर्फ सत्ता में भागीदारी से नहीं आता, क्योंकि पूंजीवादी, सामंती समाज में सत्ता का स्वरूप अंततः विषमतामूलक और वर्चस्ववादी होता है। बुनियादी बदलाव असल में बिना बदनामी और बलिदान के संभव नहीं है। बुनियादी बदलाव के लिए समर्पित, संघर्षशील अगुआ व्यक्ति को दैवीय बनाकर 'मसीहा, महामानव' कहना या भगवान बना देना निरीह अज्ञानता, विज्ञान विरोधी, जनविरोधी सोच है। इससे समाज में जड़ता और रूढ़िवादिता मजबूत होती है। जनसंघर्ष को कमतर कर दिया जाता है। इंसान जन्म से नहीं,कर्म से बड़ा बनता है। परिस्थितियां उसे महान बनने का अवसर प्रदान करती हैं। जन साधारण के बीच से यदि कोई जनता के दुख दर्द को ठीक से समझे, जनता के हक और अधिकारों के लिए सार्थक और सतत प्रयास करे, भ्रष्ट और लालची नहीं बने, बदनामी सहन कर सके, जरूरत पड़ने पर बलिदान दे सके तो वह व्यक्ति महान बनता है, दुनिया में नाम कमाता है।

यह भी गौरतलब है कि किसी नायक की व्यक्ति पूजा करना भी उचित नहीं है जैसा बाबा साहेब ने भी कहा है क्योंकि इससे तानाशाही पनपती है, मिथ्या अवतारवाद को बढ़ावा मिलता है। आमजन में जनसंघर्ष के प्रति उदासीनता पनपती है। फुले, अंबेडकर जैसे क्रांतिकारी नायकों ने ईश्वर, अल्लाह के आदेश से नहीं, बल्कि अपने समय की परिस्थितियों को इंसान की बेहतरी के लिए बदलने की कोशिश हेतु अपने ज्ञान, विवेक का बेहतरीन इस्तेमाल किया था, संगठन बनाकर बुनियादी बदलाव के प्रयास किए थे।

भारत को शोषणमुक्त, समतामूलक बनाने के लिए आर्थिक शोषण के साथ-साथ जातिगत भेदभाव और शोषण से भी मुक्ति अत्यंत जरूरी है। साथ ही महिलाओं के साथ भेदभाव, धर्म के नाम अल्पसंख्यकों के प्रति नफरत के खिलाफ भी बोलना जरूरी है। क्योंकि वोट की खातिर हिंदू मुसलमान के बीच भड़काए दंगों में दलितों का इस्तेमाल बड़े स्तर पर होता है, दलितों में भी वाल्मीकि जैसी सबसे पिछड़ी जाति का। जाति विशेष की 'महापंचायतों' ने समाज में कट्टरता और ध्रुवीकरण बढ़ाया है जिससे समाज में संवादहीनता की स्थिति बन गई है। रोजी-रोटी के लिए साझा संघर्ष कमजोर हुआ है।

खास चिंता की बात यह है कि समतामूलक भारत बनाने के लिए मार्गदर्शक हमारे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष संविधान और लोकतंत्र पर हमले तेज हो रहे हैं। ये हमले मुख्यतः पूंजीपति हितैषी, जाति,जेंडर आधारित विषमता एवं वर्चस्व की पोषक सांप्रदायिक राजनीति एवं विचारधारा द्वारा किए जा रहे हैं। इसलिए इन हमलों के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाना भी हमारा आज का परम नागरिक कर्तव्य है।

देश आजाद हुए 75 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, लेकिन चिंता की बात है कि महात्मा फुले और अंबेडकर के सपनों का भारत हम बना नहीं पाए। आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए प्राकृतिक संसाधनों के बेरहमी से दोहन के परिणामस्वरूप हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था तो जरूर बन गए हैं लेकिन मानव विकास सूचकांक में इंडिया का स्थान आज भी 131वां है। वैश्विक भूख सूचकांक में हम 94वें पायदान पर हैं। आर्थिक विषमता तेजी से बढ़ी है। आबादी का 10 प्रतिशत सबसे उच्च वर्ग आज इंडिया की 77 फीसद दौलत का मालिक बन गया है। सतत विकास के मानकों में हमारा स्थान 193 देशों की सूची में 117वां है। जेंडर समानता की दृष्टि से इंडिया का स्थान 156 देशों में 140वां है। डेमोक्रेसी इंडेक्स में 167 देशों की सूची में 53वां है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के तहत 180 देशों की सूची में इंडिया का स्थान 142वां है।

निजीकरण के कारण आरक्षण अर्थहीन हो चला है। शिक्षा व स्वास्थ्य का तेजी से निजीकरण हुआ है। आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी शिक्षा पर जीडीपी का लगभग तीन प्रतिशत और स्वास्थ्य पर जीडीपी का करीब दो प्रतिशत ही व्यय है। बेरोजगारी तेजी से बढ़ी है। करीब 35 प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं। किसान व मजदूर बदहाल हैं। राजनीति में बढ़ते धनबल एवं अपराधीकरण ने लोकतंत्र को बुरी तरह कमजोर कर दिया है। जाति व धर्म के नाम नफरत और हिंसा तेजी से बढ़ी है। विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा नागरिक अधिकारों के लिए संघर्षशील बुद्धिजीवी, मानव अधिकार एवं विद्यार्थी कार्यकर्ता, यहां तक पत्रकारों को भी बदनाम यूएपीए कानून का दुरुपयोग कर प्रताड़ित किया जा रहा है। नागरिकों की निजता खतरे में है। असल में क्रोनी कैपिटलिज्म एवं जाति, धर्म के नाम विभाजन की राजनीति ने हमारी आज़ादी को खतरे में डाल दिया है। संविधान व लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। पूंजीवादी विकास के चलते आदिवासी जल, जंगल व जमीन के पुश्तैनी हक से वंचित हो रहे हैं। महिला उत्पीड़न बढ़ा है।

दलित उत्पीड़न थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजस्थान पुलिस की ताजा क्राइम रिपोर्ट बताती है कि दलितों पर पिछले तीन वर्षों में अत्याचार की घटनाओं में करीब 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2020 में अत्याचार के दर्ज प्रकरण 7117 से बढ़कर वर्ष 2022 में 8752 हो गए। पिछले एक वर्ष में दलित उत्पीड़न के दर्ज प्रकरणों में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दलितों की हत्या की घटनाएं वर्ष 2020 में 84 से बढ़कर वर्ष 2022 में 99 हो गई। दलित महिलाओं से बलात्कार के वर्ष 2020 में 476 प्रकरण दर्ज हुए थे जो वर्ष 2022 में बढ़कर 658 हो गए। दलित उत्पीड़न के दर्ज कुल अपराध 8752 में से 4198 अर्थात करीब 55 प्रतिशत प्रकरण पुलिस जांच में झूंठे साबित किए गए। इन तीन वर्षों में एससी एसटी एक्ट में दर्ज कुल प्रकरण 101 में से 58 अर्थात 66 प्रतिशत जांच में झूँठे बताए हैं। दलित महिलाओं से बलात्कार के दर्ज प्रकरण पुलिस ने जांच में 48 प्रतिशत झुंठे बताए हैं।

माना कि अंधेरा अब तो और घना होता जा रहा है लेकिन उम्मीद की किरण यह है कि संविधान एवं लोकतंत्र को बचाने के लिए जनता का जागरूक हिस्सा आज भी मशाल जलाए हुए है, संघर्षरत है। किसान, मजदूर, छात्र-युवा, दलित, आदिवासी, महिलाएं और बुद्धिजीवी अपने नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं। फुले और अंबेडकर की वैचारिक विरासत को बचाने के लिए हमें विषमतामुलक पूंजीवाद और जाति, जेंडर आधारित भेदभाव के खिलाफ साझा संघर्ष तेज करना होगा।

–डॉ. रमेश बैरवा,
प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान एवं प्रदेश सह संयोजक
दलित शोषण मुक्ति मंच राजस्थान

मसूदा एस.डी.एम. पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

- **कलेक्टर ने एस.डी.एम. को सूचना देने के दिए आदेश के बाद भी नहीं दी सूचना**
- **राज्य सूचना आयोग ने प्रार्थी को समय पर सूचना नहीं देने के कारण जुर्माना लगाया**
- **21 दिवस में प्रार्थी को निःशुल्क सूचना उपलब्ध करवाने के भी आदेश दिए**

मसूदा, (निसं)। राज्य सूचना आयोग ने प्रार्थी को समय पर सूचना नहीं देने के कारण मसूदा उपखंड अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट को 25 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। मामला मसूदा उपखंड क्षेत्र के ग्राम सतावडिया के पीड़ित प्रार्थी देवीलाल द्वारा मांगी गई सूचना से जुड़ा हुआ है।

प्रार्थी के अधिवक्ता भरत सिंह सौलंकी ने बताया कि प्रार्थी देवीलाल पुत्र रघुनाथ निवासी ग्राम सतावड़िया ने सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी से सूचना मांगी थी,पर सूचना नहीं दी। प्रार्थी द्वारा जिला कलेक्टर अजमेर को अपील की गई। जिला कलेक्टर अजमेर ने उपखण्ड अधिकारी को तत्काल सूचना उपलब्ध करवाने हेतु आदेश दिया था। परन्तु उपखण्ड अधिकारी ने जिला कलक्टर अजमेर के आदेशों की भी पालना नहीं की। प्रार्थी को सूचना नहीं मिलने पर प्रार्थी ने राज्य सूचना आयोग में अपील की। प्रार्थी की अपील पर सुनवाई के दौरान राज्य सूचना आयुक्त ने मसूदा उपखण्ड अधिकारी मसूदा को सूचना के अधिकार अधिनियम की पालना नहीं करने तथा कर्तव्य पालन में घोर लापरवाही बरतने का दोषी मानते हुए सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 के तहत 25 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया। इसके साथ ही 21 दिवस में प्रार्थी को निःशुल्क सूचना उपलब्ध करवाने के भी आदेश दिए। मामला वर्ष 2021 - 22 का होने से उस समय उपखंड अधिकारी के पद रहे संबंधित अधिकारी को यह जुर्माना भरना पड़ेगा।

हाईकोर्ट ने रिक्त पदों पर भर्ती मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा

- **राज्य के जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पदों पर भर्ती का मामला**
- **राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन द्वारा दायर जनहित याचिका पर बहस हुई**

जोधपुर, (कासं)। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एम एम श्रीवास्तव और न्यायाधीश कुलदीप माथुर ने राज्य सरकार को निर्देश दिए है कि राज्य के जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पदों पर भर्ती तथा जोधपुर में राज्य आयोग की स्थाई पीठ गठित करने बाबत दो सप्ताह में न्यायालय को पूरी स्थिति से अवगत कराएं।

राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन द्वारा दायर जनहित याचिका पर बहस करते हुए अधिवक्ता अनिल भंडारी ने कहा कि गत 13 दिसंबर को खंडपीठ ने जोधपुर में राज्य आयोग की स्थाई पीठ गठित करने की आवश्यकता बताते हुए जिला और राज्य आयोग में समुचित सुविधाएं और स्टाफ नियुक्ति के निर्देश दिए थे और राज्य के जिला आयोगों में लंबे समय से अध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पदों पर भर्ती नहीं किए जाने पर नाराजगी जाहिर की थी। अधिवक्ता भंडारी ने कहा कि अक्टूबर माह में 16 अध्यक्ष और 10 सदस्यों की भर्ती के साक्षात्कार पूर्ण हो जाने पर भी 12 अध्यक्ष और 9 सदस्यों की ही भर्ती की गई। उन्होंने कहा कि तीन जगह पर अध्यक्ष और 23 सदस्यों के पद इसी माह रिक्त हो रहे है, लेकिन अभी तक राज्य के उपभोक्ता मामलात विभाग ने रिक्तियां भी घोषित नहीं की है, जबकि नियमानुसार छह माह पूर्व ही रिक्तियां घोषित होकर समय पर भर्तियां की जानी थी। उन्होंने कहा कि इस वजह से कई जिला आयोग में कोरम के अभाव में न्यायिक कार्रवाई ठप हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जोधपुर के उपभोक्ता परिसर में अभियोजन विभाग के उप निदेशक कार्यालय को खाली करवाया जाएं, क्योंकि उनका तीन मंजिला भवन बन कर शुरू हो चुका है और ऐसा किए जाने से उपभोक्ता आयोग और परिवादियों को काफी सुविधा होगी। राज्य सरकार की ओर से रजत अरोड़ा, हाईकोर्ट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. सचिन आचार्य और भारत सरकार की ओर से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल मुकेश राजपुरोहित ने पैरवी की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एम एम श्रीवास्तव और न्यायाधीश कुलदीप माथुर ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि नियुक्तियों तथा रिट याचिका में चाहे गए सभी अनुतोष बाबत न्यायालय को दो सप्ताह में प्रगति से अवगत कराएं।

कोटा में सस्ती व अच्छी कोचिंग देने की शुरूआत

- **'कोटा वाला कोचिंग' से मात्र पांच रूपये फीस में तीनों विषयों की कोचिंग**

कोटा, (निसं)। 'पापा भरेंगे फीस शान से, बच्चे पढ़ेंगे स्वाभिमान से' इस उद्देश्य के साथ शिक्षा नगरी में हर वर्ग के विद्यार्थियों को 'कोटा वाला कोचिंग' संस्थान द्वारा मात्र 15 रूपयें फीस में इंजीनियरिंग व मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के लिये क्लासरूम कोचिंग दी जायेगी।

इस वर्ष देश में 40 शहरों सहित राजस्थान के तीन शहरों कोटा, जयपुर व सीकर में इसके अध्ययन केंद्र खोले जा रहे हैं। 'कोटा वाला कोचिंग' के निदेशक राजेश गांधी ने बताया कि वे 2013 से 'अफसर बिटिया' अभियान में गुजरात व महाराष्ट्र में गरीब बेटियों को अफसर बनाने के लिये पढ़ाई का कार्य कर रहे हैं। आज देश के सभी राज्यों से प्रत्येक वर्ग के बच्चे कोटा आकर क्वालिटी कोचिंग लेना चाहते हैं लेकिन यहां के कोचिंग संस्थानों में महंगी फीस, हॉस्टल व मैस खर्च का सालाना बजट 3 से 8 लाख रूपयें तक पहुंच जाता है, जो गरीब अभिभावकों के लिये चिंता का विषय है। वे जमीन या जेवर गिरवी रखकर या कर्ज लेकर बच्चों को कोटा में कोचिंग के लिये भेज रहे हैं।

पहले वर्ष कोटा में दो अध्ययन केंद्र-कोको के वाइस प्रेसीडेंट एकेडेमिक अमित ने बताया कि सामाजिक सरोकार के तहत सभी वर्गों के बच्चों को नाममात्र शुल्क पर स्तरीय क्लासरूम कोचिंग देने के उद्देश्य से 'कोटा वाला कोचिंग' की शुरूआत की गई है। शहर के राजीव गांधी नगर एवं रोड़ नंबर-2 इंडस्ट्रियल एरिया, विज्ञाननगर में दो अध्ययन केंद्रों पर पहले वर्ष 4 हजार बच्चों को ऐसे 16 अनुभवी फैकल्टी पढ़ायेंगे जिन्हें 10 वर्ष से पढ़ाने का अनुभव है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी प्रत्येक विषय की कक्षायें 90 मिनट की होंगी, जिससे सिर्फ 15 रूपयें शुल्क में बच्चे साढ़े चार घंटे क्लासरूम कोचिंग ले सकेंगे।

वाइस प्रेसीडेंट मार्केटिंग व प्रशासन राम किशोर शर्मा ने कहा कि गांव के विद्यार्थियों में काबिलियत है, वे कोटा वाला कोचिंग पर नगण्य शुल्क में स्वाभिमान के साथ पढ़ेंगे।

कोचिंग के निदेशक राजेश गांधी ने बताया कि काउंसलिंग सेशन में भाग लेने वाले कक्षा-8वीं से 12वीं पास विद्यार्थियों को इंटरनेट सुविधा के लिये 2 जीबी क्षमता का कार्ड निशुल्क दिया जायेगा। जिससे वे जेईई-मेन तथा नीट की अधिकृत वेबसाइट से परीक्षा संबंधी सारी जानकारियां निशुल्क प्राप्त कर सकेंगे।

रक्षिता राठौड़ नौ सेना में सब लैफ्टिनैंट बनी

जोधपुर, (कासं)। मारवाड़ की बेटी रक्षिता राठौड़ ने नौ सेना में सब लैफ्टिनैंट तकनीकी अधिकारी बनकर प्रदेश, मारवाड़ तथा समाज का नाम रोशन किया है। रक्षिता राठौड़ नौ सेना में सब लैफ्टिनैंट तकनीकी अधिकारी बनने वाली राजस्थान की पहली बेटी है। नागौर के परबतसर के खानपुर गांव की रक्षिता राठौड़ पुत्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ भारतीय नौ सेना में सब लैफ्टिनैंट बनी है। भारतीय नौ सेना में तकनीकी अधिकारियों (आईटी) का यह पहला महिला बैच है।

रक्षिता राठौड़ राजस्थान की पहली बेटी है, जो 20 वर्ष की आयु में भारतीय नौ सेना में तकनीकी अधिकारी बनी है। आई एन एस वलसुरा, नौ सेना एकेडमी जामनगर में हुई पासिंग आउट परेड के बाद रक्षिता नौसेना में सब लैफ्टिनैंट बनी है। रक्षिता ने नौ सेना महिलाओं के तकनीकी विंग में प्रदेश की पहली महिला अधिकारी बन कर राजस्थान और पूरे राजपूत समाज को गौरवान्वित किया है।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

मंगलवार 11 अप्रैल, 2023

वैशाख मास, कृष्ण पक्ष, पंचमी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2080, ज्येष्ठा नक्षत्र दिन 12:18 तक, वारियान योग सांय 5:52 तक, तैतिल करण प्रातः 7:18 तक, चन्द्रमा दिन 12:58 से धनु राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थितिः सूर्य-मीन, चन्द्रमा-वृश्चिक, मंगल-मिथुन, बुध-मेष, गुरू-मीन, शुक्र-वृष, शनि-कुम्भ, राहु-मेष, केतु-तुला राशि में।

आज कुमार योग दिन 12558 से आरम्भ होगा और रवियोग दिन 12:58 से आरम्भ होगा और दुग्ध योग सूर्योदय से प्रातः 7:18 तक है। आज महात्मा ज्योतिबा फुले जयन्ती है। आज षष्ठि तिथि का क्षय हुआ है।

सर्वश्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:20 से 10:54 तक, लाभ-अमृत 10:54 से 2:03 तक, शुभ 3:37 से 5:12 तक।

राहूकालः 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 6:11, सूर्यास्त 6:45

मेष

अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। पारिवारिक कार्यों के लिए भागदौड़ रहेगी। दिन के मध्यान्ह पश्चात नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

वृष

अपने आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। दिन के मध्यान्ह पश्चात अष्टम चन्द्र शुभ नहीं है।

मिथुन

परिवार में चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होंगे। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। दिन के मध्यान्ह पश्चात परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

कर्क

परिजनों के व्यवहार के कारण मन खिन्न हो सकता है। आपसी ईर्ष्या-वैमनस्यता के कारण परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। व्यावसायिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी।

सिंह

घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कन्या

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। घर-परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

तुला

व्यावसायिक कार्यों से संबंधित वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है।

वृश्चिक

अपने अति आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। आवश्यक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे।

धनु

घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। दिन के मध्यान्ह पश्चात परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मकर

आर्थिक/वित्तीय मामलों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। दिन के मध्यान्ह पश्चात अनर्गल कार्यों में समय खराब होगा। मन में असंतोष बना रहेगा।

कुंभ

व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। अटके हुए कार्य शीघ्रता से बनने लगेंगे। नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा।

मीन

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।